जागो आमंत्रण

अक्टूबर – दिसंबर २०२१
अंक – चार
मूल्य – ६० रुपये

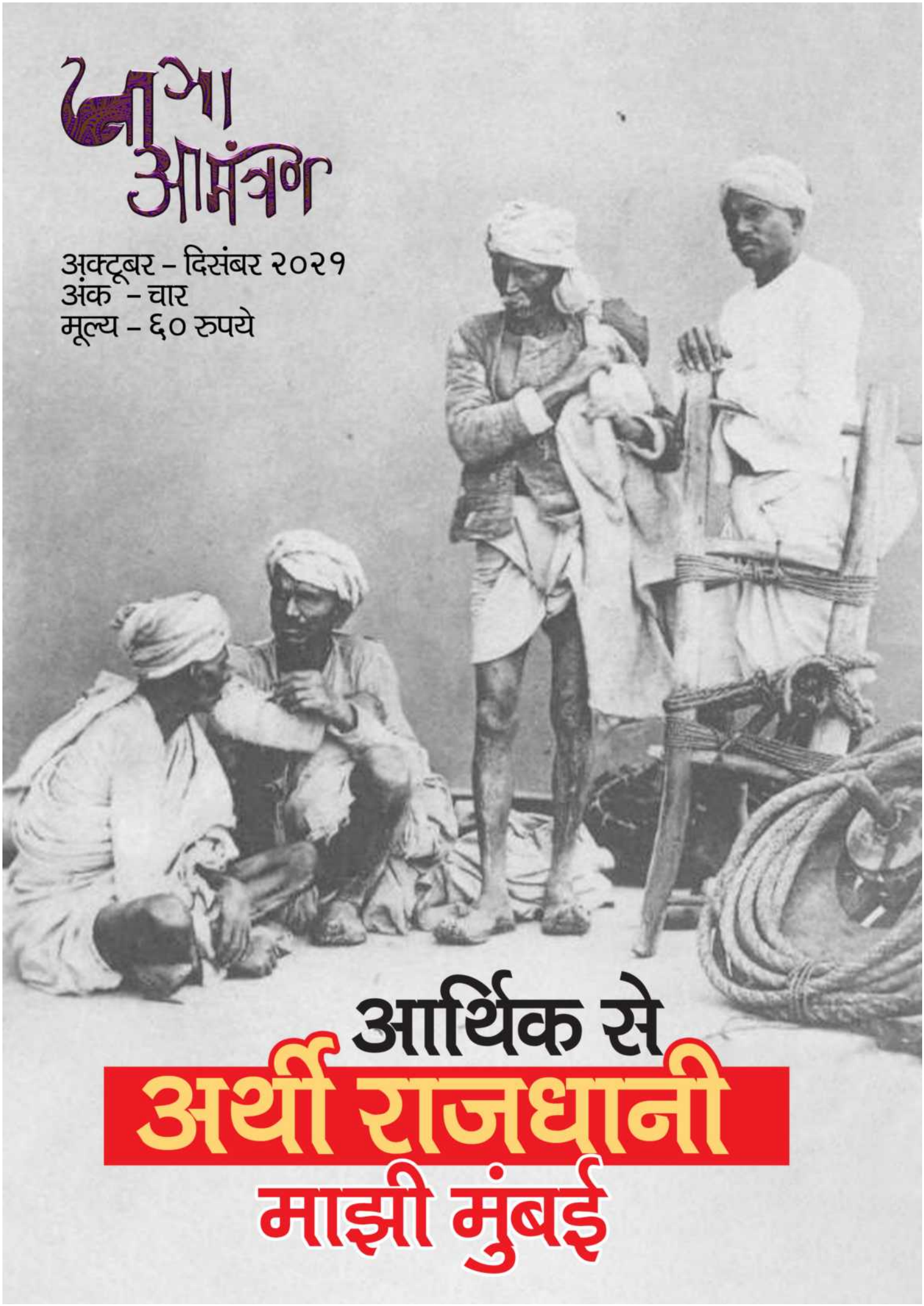

आर्थिक से अर्थी राजधानी माझी मुंबई

इजारा

आज किसके साथ TRY किया

खजूर की चटनी

गुड़ और इमली के साथ

100% Natural products

Try this chutney with Samosa, Kachori, Bread Pakoda, Paratha, Dal Rice and Bhel etc.
Also use this as an alternate of achar/Sauce/Jam

DATES CHUTNEY WITH JAGGERY

MARKETED BY
IJAARA FOODS
B 121, Green Field Colony Faridabad, Haryana 121001
Follow us @ijaarafoods

For Bulk Purchasing / Distribution
+91 99712 29644
ijaarafood@gmail.com
www.willindiachange.org

A NGO Initiative to empower women

THIS DIWALI ORDER ORGANIC & PURE AUTHENTIC SWEETS

www.willindiachange.org

इजारा
महिलाओं द्वारा संचालित भोजनालय

Follow us @ijaarafoods

INDIA'S ONLY SWEET
WITH MULTIPLE HEALTH BENEFITS

Sweet preparation based on Ancient Nutritional Science
Health benefit including Improve Digestion, Get Protein, Calcium, Iron, & Improve Memory.

KARANJI
₹ 349/-

RAVA LADDU
₹ 439/-

SHANKARPALI
₹ 419/-

BESAN LADDU
₹ 549/-

BUNDI LADDU
₹ 449/-

- Delivery through courier or take away or delivery boy
- Charges extra beyond 2 KM
- All prices 1 kg
- Advance payment through पे

ALL WOMEN KITCHEN

A NGO INITIATIVE TO GIVE LIVELIHOOD TO WOMEN.

7758968909 | 9971229644

189/10, sector one, Charkop, Kandivali West, Mumbai 61

WE ALSO WELCOME CORPORATE/BULK BOOKING FOR GIFTING PURPOSE

कवर पेज चित्र

साणे गुरूजी ने खानदेश में किसानो के लिए आंदोलन चलाया था। उस समय भारत में अंग्रेजी सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स किसानो से मिलता था और इन्हे अंग्रेजी में Peasant कहते है। दरसअल अर्थ व्यवस्था पहले खेती से तय होती थी और 1938 में किसानो की फसल बरसात में खराब हो गई थी। तब कर माफी को लेकर बडा आंदोलन चला।

- **Pune Bureau Chief**
  Nitin Kalje
- **Mumbai Head :**
  Narender Patil
- **Senior Correspondence**
  Suhasini Sakir
- **IT head –**
  Shantanu Chauhan

- **Editorial Team**
  Chief Editor
  Biswadeep Roychowdhury
- **Consulting Editor**
  Mohammad Ismail
- **Honourable Advisor**
  Gaur Kanjilal
  Executive Director, Indian Association of Tour Operator
- **Legal Advice & UP Head**
  Pratap Singh Chandel
- **Copy Editing**
  Yash Bhardwaj
- **Graphic Designer**
  Sanket Mangale
- **Video Editor & Delhi Head**
  Kapil Attari
- **Special thanks to**
  Dr Biswaroop Roychowdhury & Mr Shankar Korenga
  Mr Rajan Shellar – PRO - MSRTC
  Mr Imtiyaz Ansari – AIMIM
  Ms Neha Grover – National Restaurant Association of India
  Eknath Pawar - Praja Foundation

- Mail us or included your name in our free circulation list/ Send press release at / yatraamantran@gmail.com
- Advt related queries/ mail us at Biswadeep96@gmail.com
- Visit us or download the pdf copy at www.yatamantran.com
- Watch all the video and other stories at **You Tube Channel – Asatya Bharat**

• Publisher Address
B 121, 2nd Floor, Green Field Colony , Faridabad, Haryana -121001

संपादकीय

मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है , यह कोई नई बात है नहीं , नई बात तो यह है की कैसे यह बर्बादी की तरफ जा रही है। आप बताये किसी शहर की बुनियाद क्या है। जवाब कुछ भी हो सकता है पर गौर करे तो वहा के प्रवासी वहा के लिए सबसे जरूरी है। मसलन सूरत में ढाई लाख प्रवासी मजदूर तालाबंदी के कारण गांव चले गए , लिहाजा वहा के हिरा कारोबार प्रभवित हो गया। इसी तरह से मुंबई के धारावी से 50 हजार मजदूर चले गए तो वहा का हीरा कारोबार शून्य पर आ गया। अगर आपको किसी शहर की अर्थ व्यवस्था को हाशिये पर लाना है तो कुछ ऐसा कीजिये की वहा से प्रवासी का पलायन हो जाये। तालाबंदी के बाद चाहे दिल्ली हो या मुंबई , प्रवासी मजदूर शहर छोड़ने को मजबूर हुए । यह तो अब तक साबित नहीं हो सका है की तालाबंदी से कितना कोरोना के कीटाणु काबू में आ सके है पर शहर और उसकी आर्थिक क्षमता दम तोड़ चुकी है। दरसअल समझेंगे तो पता चलेगा की निवासी शहर नहीं चलाता है , शहर प्रवासी चलाता है। तो तालाबंदी से प्रवासी को खदेड़ दिया गया , बचा निवासी ।वह अकेला क्या करेगा। मुंबई में सताइस प्रतिशत प्रवासी शहर छोड़ चूका है और निवासी अपने गुरबत के दिन गिन रहा है । अब मंडप डेकोरेटर हो या सिनेमा मालिक ,या बॉलीवुड या शराफा बाजार या रिटेल कारोबार , सबके बुरे दिन आ गए। तालाबंदी क्यों की गयी अब आपके भी समझ में आ रहा होगा । बाकी मैगजीन पढ़िए ताकि मुंबई की नई बात से आपका परिचय हो सके।

बीस्वदीप रॉय चौधुरी
मुख्य संपादक

मुंबई पर वैक्सीन की जबरदस्ती क्यों ?

पिछले डेढ़ सालो से मुंबई लोकल मानो किसी के बाप की जागीर हो गयी है जो बता रहा है की क्या करना पड़ेगा ताकि आप इसमें सफर कर सके। यात्रा आमंत्रण पूछना चाहता है की क्या बीमारी के आड़ में वैक्सीन को बेचा जा रहा है या बीमारी के आड़ में कालाबाजारी की जा रही है या बीमारी के आड़ में गुलामी दी जा रही है या बीमारी के आड़ में गरीबी परोसी जा रही है या बीमारी के आड़ में मौलिक अधिकार छीने जा रहे है या बीमारी के आड़ में निराधार फैसले लिए जा रहे है।

हाल ही में इंडियन बार काउन्सिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलेश ओझा के मार्गदर्शन में ने एक जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका में मुंबई लोकल में सफर करने के लिए जारी आदेश जिसमे कहा गया है की दो डोज टीका लगवा चुके नागरिक ही ट्रेन की सवारी करेंगे , के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दी है। पहली बात देश में ऐसे फैसले लिए जा रहे है जो सरासर संविधान में सुनिश्चित हमारे अधिकारों का हनन है।

19 मार्च 2021 को भारत सरकार ने यह साफ कर दिया था की वैक्सीन पूरी तरह से स्वैछिक है और लाभार्थी अपने विवेक से इसको लेने के विषय में निर्णय ले सकता है। इसके अलावा वैक्सीन लेने के बाद अगर किसी तरह का दुष्परिणाम होते है तो वैसी स्थिति में किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। यही जानकारी अलग अलग आर टी आई में उल्लेखित है। अलग अलग राज्यों के उच्च न्यायालय जैसे गुवाहाटी , मेघालय , मिजोरम ,अरुणाचल प्रदेश ने अपने आदेश में कहा है की टीका को किसी भी सार्वजनिक परिवहन या स्थान में आवश्यक नहीं किया जा सकता है और न ही इसको लेकर किसी भी प्रकार का भेद भाव किया जा सकता है। इसके अलावा टीका अभी भी प्रयोग के मंच पर ही है और अभी भी इसका तीसरा वैज्ञानिक परीक्षण होना बाकी है। यानि टीका अभी भी पूरी तरह से कारगर नहीं है और इस से कई प्रकार की शारीरिक हानी जैसे मौत होने की भी सम्भावना है।

महाराष्ट्र सरकार ने आदेश दिया है की लोकल ट्रेन में वही सफर करेंगे जो टीका ले चुके है। इसके अलावा मॉल में सभी कर्मचारी ओ को टीका लेना आवशयक है। जो नागरिक माल में आना चाहते है उन्हें भी टीका लेना होगा। क्या ऐसा करने से कोरोना से बचा जा सकेगा। जो शोध हुए है वह बताते है की वैक्सीन लेने से कोरोना न होने की की गारण्टी नहीं है। हाल ही में ICMR के प्रबंध निदेशक ने माना की टिका लेने के बाद भी कोविद हो सकता है। टीका का मतलब कोविद न होना नहीं है।

केरल में टीका ले चुके 40 हजार लोगो में कोविद के लक्षण पाए गए है। बनारस हिन्दू विश्विद्यालय में 1500 पर टीका लेकर प्रयोग किया और पाया की इनमे से 1400 ने दो डोज वैक्सीन लिया और उनमे से 18 प्रतिशत में कोविद के लक्षण देखे गए। इजराइल में हॉस्पिटल आ रहे ज्यादातर वही मरीज है जो टीका के दोनों खुराक ले चुके है। एक और शोध में 377 डॉक्टर में से 131 डॉक्टर को वापस कोविद हुआ। बैंगलोर में जुलाई के महीने में हॉस्पिटल में आ रहे 56 प्रतिशत वही लोग है जो टीका ले चुके है। इंग्लैंड में 50 प्रतिशत संक्रमण के मामले टिका ले चुके नागरिको से आ रहे है। भूटान ने 67 प्रतिशत को एक ही हफ्ते में टीका दिलवा दिया। पर उसके बाद से केसेस का बढ़ना शुरू हो गया।

कोविद काल में डॉक्टर बिस्वरूप ने पहले ही बता दिया था की टीका का कोई मतलब है नहीं और न ही इस से किसी भी प्रकार से बचाव की उम्मीद की जा सकती है।बल्कि अब हर तीन महीने में एक खुराक टीका का लेते रहो आजीवन।

वही दूसरी तरफ ऐसे यात्रिओ की भी सख्या लगातार बढ़ती जा रही जो टिकट न मिलने से बिना टिकट यात्रा करने को मजबूर है। हम ऐसे यात्री को बेटिकट नहीं कह सकते है और न ही इनसे किसी भी तरह का जुरमाना लिया जा सकता है क्युकी इनको टिकट दिया नहीं गया है। मुंबई लोकल ने 8 करोड़ 15 लाख इस साल जुर्माने के तौर पर वसूला। वही मुंबई लोकल को तकरीबन 1200 करोड़ का नुकसान लोकल ट्रेन न चलने या सिमित लोगो को यात्रा अनुमति देने के कारन उठाना पडा। तो सवाल वही की जो मेरा है और मेरे दिए टैक्स से चल रहा है उस सुविधा को देने से कैसे मना कर सकते है।

और आखरी बात , अगर वैक्सीन से किसी को कोई भी शारीरिक क्षति होती है या मृत्यु हो जाती है तो जो वैक्सीन का आदेश दे रहा है यानि राज्य सरकार , क्या वह इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेंगे। अगर नहीं तो वैक्सीन की जबरदस्ती कैसे की जा सकती है या इसको हमारे ऊपर जबरदस्ती कैसे लाद सकते है। क्युकी वैक्सीन से मौते भी हो रही है और दुष्परिणाम भी देखे जा रहे है।

योहान टेंगरा

सदस्य, एआईएम

आज हमारी आजादी छीनी जा रही है। हमारी सास लेने की आजादी , हमारी यात्रा करने की आजादी, व्यापार करने की आजादी,हमारे शरीर में क्या जाना चाहिए और क्या नहीं, वह आजादी भी हमसे छीनी गई है।

सलीम भाटी

कार्यकारी अध्यक्ष , जनता दल यूनाइटेड , मुंबई

कोरोना एक सोची समझी सियासत जैसा प्रतीत हो रहा है। वैक्सीन लेने से कोरोना के बचाव की पक्की गारंटी न होने के बाद भी लोकल में इसे जबरदस्ती लागू किया जा रहा है। इस वक्त मजदूर बेहाल है और अम्बानी अडानी के पास हर तरह की सुविधा मौजूद है। मेरी राय सरकार हमारी कमाई से हमारे ऊपर जुल्म कर रही है और जाच एजेंसी के माध्यम से चीजो पर नियंत्रण कर रही है।

गैर निष्पादित मुंबई

शिवसेना का आपला दवाखाना हुआ फैल। ठाणे महानगपालिका की इस योजना पर 160 करोड़ खर्च होना था। 70 हजार मरीजो के इलाज के बाद भी घोटालो के चलते इस योजना को ठन्डे बस्ते में डाल दिया गया। योजना में 10 रुपये में इलाज का वादा था और निजी कंपनी की भागीदारी शामिल थी।

अवैध निर्माण बनती जा रही है मुंबई की नयी पहचान

किसी शहर में नागरिक कहा और किस हाल में रह रहे है , तय करता है वह का जीवन शैली। पिछले दो दशक में दो बाते मुंबई के सन्दर्भ में हुई , पहला जनसख्या में तेजी से इजाफा और दूसरा मकानों की कीमतों में उछाल। तो जो नौकरी , काम धंधे के लिए आ रहा है वह कहा रहेगा। सस्ते मकान है नहीं और आमदनी इतनी है नहीं की मेहंगे आवास का रुख करे। लिहाजा अवैध मकान का विकल्प चल निकला। मुंबई कहने को तो आर्थिक राजधानी है पर यहाँ पर 60 प्रतिशत लोग झोपड़पट्टी में रहते है बेहद ही अमानवीय परिस्थिति में। यह झोपड़पट्टी जयादातार सरकारी जमीन पर कच्चे और अस्थाई निर्माण के रूप में होते है। यहाँ जीवन इतना मुश्किल की 89 प्रतिशत लोगो की मृत्यु के पीछे श्वास सम्बन्धी रोग है। अवैध आवास और अवैध अतिक्रमण मुंबई की नयी पहचान है। मुंबई में ऐसे 2 लाख से जयादा लोग है जिनके पास यह झोपड़पट्टी भी नहीं है। यह बेघर लोग है जो सडको पर रहते है। सरकार कह तो देती है की तालाबंदी है , कोई बाहर न निकले तो जिनका बाहर ही घर है वोह कहा जाये। और जो तंग गालिओ और मुश्किल से सर छुपाने की जगह पर है वह कौन सी सामाजिक दुरी का पालन करे। दरसअल प्रशासन के लिए यह मसला है ही नहीं क्युकी धारावी के इन्ही इलाको ने नया पर्यटन ढूढ़ लिया है। स्लम टूरिज्म। यानि अब विदेशिओ को दिखाओ की इक्कीसवी सदी में देश के आर्थिक राजधानी में कैसी गरीबी और भुखमरी है। दिखाओ की यही है भारत की सच्चाई। कोविद काल में जब मजदूरों का पलायन शुरू हुआ तब खबर लगी की 42 लाख से जयादा लोग दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे है और राशन सिर्फ ढाई लाख लोगो तक पहुंच रहा है। पर सरकार को बस सबको घर में बंद करो और कोविद का खेल चलने दो। जो पहले से दो वक्त का ठीक से खाना नहीं जुटा पाता है उसे कोविद के नाम पर और गरीबी दी जा रही थी। तो गरीब अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेता है। जो आकड़े है वह बताते है की सिर्फ कोविद के समय 10 हजार अवैध निर्माण हुए और पिछले पांच साल में 1.5 लाख अवैध निर्माण। पर गरीब ही अवैध निर्माण नहीं कर रहा है। जो ऊंची ऊंची इमारतों में रह रहे है उनके यहाँ भी यह गोरख धंधा फल फूल रहा है। ठाणे के मुम्ब्रा में नब्बे प्रतिशत इमारते अवैध है। इसी तरह से चेम्बूर , मानखुर्द , गोवंडी में 277 इमारतों के खिलाफ तोड़क करवाई के आदेश दिए।

मुंबई देश का सबसे महंगा शहर है. हमारे देश के सबसे धनवान लोग इसी शहर में रहते है और यही से बॉलीवुड भी चलता है .जनसख्या बढ़ने के साथ शहर का विस्तारीकरण भी होने लगा .नए इलाके जैसे विरार नालासोपारा नए ठिकाने बने अगस्त 2021 में एक जनहित याचिका की सुनवाई में विरार महानपालिका ने माना कि उनके शहर में 9000 अवैध निर्माण है . मुंबई उच्च न्यायालय ने इन निर्माण को ढहाने के आदेश दिए है . पर कब होगी कार्रवाई और जो जिम्मेदार है क्या उनके खिलाफ भी कोई कदम उठाये जायेंगे .इसी तरह से उल्हासनगर का भी हाल अलग नहीं है. १० हजार इमारतो के इस शहर में 95 प्रतिशत इमारते अवैध है .कोर्ट ने पाया है तकरीबन 1.5 लाख अवैध निर्माण हुए है . दुसरे शब्दों में पूरा शहर ही अवैध है . अब कौन है इस अवैध शहर का निर्माता, इस पर गहराई से जांच होनी चाहिए .अब जो दूसरा तर्क है इन इमारतो नको न तोड़ के इनको नियमित कर दिया जाये . यानि सीधे सीधे आप भ्रष्टाचार को मौका दे रहे है.

तो आप देखे , आप रहे , आप इस बात को भी सुनिश्चित कर ले कि अगर मकान खरीद रहे है तो वैध हो अवैध नहीं. वर्ना कभी आपकी कमाई पर तोड़क कारवाई हो सकती है .क्युकी कब बनी ,कैसे बनी , किसने बनाया ,कौन है इसके लिए जिम्मेदार , आप पूछते रहिये , पर यह खेल तो जरूरत के हिसाब से चलता रहेगा.

सुहासिनी साकिर के कलम से

मार्शल के नाम पर मनपा ने सड़क पर गुंडों की फौज उतारी है, यह महिलाओं से भी बतमीजी करने से पीछे नहीं हटते है, खुद मेयर कहती है की 25 हजार रोज का टारगेट पूरा करो। हम कोविद से लड़ रहें है या हफ्ता वसूली की दुकान चला रहे है। यह कौन सा मुंबई है जहा मेरे जैसे महिला पत्रकार को खुले आम सड़क पर गाली दी जाती है, यह कौन से अनपढ़ों की फौज है जो मस्क के नाम पर बतीमिजी को अपना ईमान मानते है। यह मार्शल आपराधिक मानसिकता के पेशेवर गुंडे से क्या कम है जिनके पास ना बात करने की तमीज है और ना किसी तरह की शैक्षणिक पात्रता। क्या मनपा के बेलगाम मार्शल मेरे दिए टैक्स के पैसो से सैलरी खाकर मेरे को परेशान करेंगे। और सोचे जब मेरे जैसे महिला पत्रकार और समाज सेवी को खुले आम परेशान कर सकते है बीच सड़क पर तब आम मुंबई की महिला कहा सुरक्षित है, यु भी हाल ही के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड में मुंबई महिलाओ पर होने वाले अत्याचार में दुसरे नंबर पर है। मुंबई की मेयर कोरोना के नाम पर वसूली गैंग के इन सड़क छाप गुंडों के लिए सख्त कदम उठाए। मै यह भी पूछती हु की मास्क न पहन के कौन सा गुनाह किया की मुझे फाइन भरना पड़ेगा और अगर केंद्र सरकार कहती है मास्क जरूरी नहीं तो राज्य सरकार की जबरदस्ती क्यों। और अगर लगता है की मास्क से कोरोना से बचाव होगा तो उसका सटीक वैज्ञानिक कारण भी बताये। क्युकी यह साबित हो चूका है की मास्क के कारण श्वास सम्बंधित बीमारी होने की सम्भावना है। इसके आलावा CDC की रिपोर्ट कहती है की मास्क से बीस गुना जयादा कोरोना होने के मौके है। मेयर मैडम आपके वसूली गैंग ने जो ५८ करोड़ जमा किये है उसे मैं अवैध मानती हु। क्युकी मुंबई अब वह मुंबई रही नहीं जहा पर हम अपनी आजादी से घूम सके। अब कोविड के नाम पर सिर्फ पाबंदिया है और पूछो इन पाबंदियों के पीछे का विज्ञानं तो जवाब किसी के पास नहीं। बस कहते है प्रोटोकॉल है। और इसी प्रोटोकॉल की जबरदस्ती के गिरफ्त में है मुंबई।

गैर निष्पादित मुंबई

साइकिल ट्रैक के नाम पर सामने आया मुंबई महानगपालिका की फजुल खर्ची । मुलुंड से लेकर सायन तक करोडो रुपये मंजूर किये गए। इसमें तीन स्तर में 400 करोड़ से अधिक राशि व्यय करने की योजना थी। इसमें बांद्रा , दादर, में भी इसको लागु किया जाना था।

क्या मानसून में डूबती मुंबई बनेगी

इस बार का चुनावी मुद्दा

मुंबई सपनो का शहर है , यह शहर रोजगार देता है , तरक्की देता है , आपके ख्वाब पूरा करता है। करता है या नहीं , और कितना करता है , इस मैगजीन में उसी पर बात हो रही है। मुंबई को इसी तरह से बोल के बेचा जाता है की यह शहर आपके हर अधूरे ख्वाब पूरा करता है। मानो यह अल्लादीन का जिन है जो चिराग से बाहर निकल के कहता है की जो हुकुम मेरे आका। पर शहर में कोई जिन है नहीं जो आपकी मुराद पूरी करने बैठा है। पिछले तीन दशक से मुंबई में दो चीज नहीं बदली , एक यहाँ का मानसून और दूसरा यहाँ का जल भराव। एक कुदरती है पर दूसरा क्या उसका कोई समाधान मुंबई के महानगपालिका के पास है। क्या मुंबई ही एक मात्र ऐसा शहर है जहा इतनी बारिश होती है। यूरोप में बाकायदा वाटर फ्रेमवर्क डायरेक्टिव है जिसमे हर तरह के पानी के संरक्षण पर काम किया जाता है और बाढ़ जैसे स्थिति में किस तरह के उपाय किये जाये उस पर दिशानिर्देश बनाये जाते है । पहले समझते है की इन जल भराव के पीछे की वजह क्या है। माना जाता है यहाँ की नदिया। अब तक मुंबई के नदिओं के साफ सफाई पर 400 करोड़ खर्च किये जा चुके है , जिसमे दहिसर नदी में 125 करोड़, पोइसर नदी पर 200 करोड़ और ओशिवारा नदी में 85 करोड़ खर्च हो चुके है। दरसअल हमारे यहाँ पर नदिओं में कभी भी ध्यान दिया ही नहीं जाता है। नालासोपारा के बाढ़के बाद मुंबई महानगपालिका ने 200 करोड़ पम्पिंग स्टेशन पर खर्च किया। अब तक स्टॉर्म वाटर डिस्पोजल सिस्टम पर 4500 करोड़ की राशि खर्च करने की बात कही गयी है। पर कोई लाभ नहीं हुआ क्युकी नदिओं से पानी के निकासी के 50 प्रतिशत रास्ते अवरुद्ध हो चुके है। सालाना इन जल भराव के कारण मुंबई को 28 बिलियन रुपया का नुक्सान उठाना पड़ता है। इन जल भराव से सबसे जयादा प्रभावित गरीब जनता होती है। औसतन अमीरो के मुकाबले 66: प्रतिशत नुक्सान गरीब परिवार को होता है जो झोपड़पट्टी जैसे आवास में रहते है । इन जल भराव से इस साल 33 से जयादा मौते दर्ज की गई है।

महानगपालिका को जितनी चिंता कोविद से है काश उसका एक चौथाई चिंता मुंबई के सालाना बाढ़पर करती तो मुंबई का जीवन बेहतर हो सकता था। पर लगता है की बारिश में मुंबई की जल समाधी का यह दृश्य शायद ही बदले और शायद ही इस के नाम से हो रहे भ्रष्टाचार रुके।

भिवंडी के पावरलूम उद्योग में ताला लगने की आई नौबत

साइजिंग मशीन में लगने वाले कच्चे माल और बिजली की वृद्धि ने इस उद्योग में मंडी के बादल गहरे होते जा रहे है। बता दे की पांच वर्षो से भिवंडी का यह सेक्टर अपने बुरे दिन गिन रहा है पर कोरोना ने जैसे बची खुची कसर भी पूरी कर दी। इस वक्त साइजिंग मशीन के बंद होने से तीन लाख पॉवरलूम मशीन भी बंद हो गयी। और जब मशीन ही नहीं चलेगी तो मजदूर कहा जायेंगे। लिहाजा 4 करोड़ की प्रति दिन घाटा झेल रहे इस उद्योग से 25 हजार मजदूर बेरोजगार हो गए। इस कारण से सरकार को मिलने वाले पांच प्रतिशत राजस्व भी बंद हो गया। नई टेक्सटाइल नीति न लागु हुई तो भिवंडी में इतने बड़े सेक्टर का बोरिया बिस्तर बंधना तो तय है। इसके आलावा दूसरी लहर ने कपडे से जुड़े मंगल दास कपड़ा बाजार के व्यापारी को दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया ।तालाबंदी के बाद भी राहत की उम्मीद कम ही है क्युकी कोई भी उत्सव मनाने पर रोक लगी हुई है। हम पिछले दो साल से बीमारी के नाम पर बेरोजगारी और मंदी के दानव को पाल और पोस रहे है वह स्वस्थ समाज के लिए घातक है।

श्री शंकर वी.ठक्कर

राष्ट्रीय अध्यक्ष : अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ
महानगर अध्यक्ष : कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडस

रोजगार के लिए शुरू से मुंबई में देश भर से लोग आते है । लेकिन कोरोना काल के प्रारम्भ से स्थानीय प्रशासन जिसे हम मनपा भी कहते है, ने जिस ढंग से व्यापारियों पर कहर ढाया है और लगातार दुकाने बंद रखने के निर्देश दिए गए उस से ऐसा लगता है की व्यापारियों के बर्बाद करने की कोई योजना बनी हो । लगातार दुकानें बंद करवाई गयी और ऑनलाइन व्यापार के लिए सारे रास्ते खोल दिए गए ताकि सारा मुनाफा इनको मिल सके। इन्ही कारणों से न जाने कितने व्यापारियों ने आत्महत्या की और व्यापारी पर कर्ज बढ़ता गया ।लाखो कर्मचारियों को काम से हाथ धोना पड़ा। इसके लिए जिम्मेदार कौन ? जिस व्यापारी ने लॉक डाउन की शुरू से लोगों की मदद के लिए अपने भंडार खुले कर दिए एवं लोगों को दवाइयों से लेकर जो भी आवश्यक वस्तुएं की आपूर्ति निर्बाध तरीके से अपनी जान की परवाह न करते हुए की उस व्यापारी पर इतना बडा संकट आने पर भी सरकार ने या प्रशासनिक व्यवस्था ने कभी अच्छी नजर से देखा तक नहीं है।

गैर निष्पादित मुंबई

मुंबई की सडको पर 24 साल में 21 हजार करोड़ खर्च हो गए है। इसके बावजूद मुंबई के सडको में 25 हजार गड्ढे है जो गंभीर दुर्घटना की वजह बन सकती है। हर एक गड्ढे को भरने के लिए मुंबई महानगपालिका 14 हजार खर्च कर रही है। हर साल के मानसून में इन किये गए खर्च की पोल खुल जाती है।

घाटे में डूब चुकी है लाल परी

महाराष्ट्र की जीवन रेखा यहाँ का राज्य सरकार की परिवहन सेवा है। पर वर्तमान में यह सेवा आर्थिक नुक्सान से गुजर रहा है। जो आकडे है वह बताते है की कोविद काल में 6500 करोड़ का नुक्सान परिवहन सेवा को हो चुका है और मार्च 2020 से पहले 3500 करोड़ का नुक्सान हो चूका है। तकरीबन परिवहन सेवा के तिजोरी से 9500 रुपये का घाटा हो चूका है। इस घाटे में 2750 करोड़ का नुक्सान सिर्फ कोविद के नियमो के कारन हुआ। क्युकी परिवहन की बस कोविद से पहले जहा 55 लाख किलोमीटर चलती थी वही कोविद नियम के कारण 21 लाख किलोमीटर का सफर ही कर पाई। यानि पहले रोज 21.65 करोड़ का राजस्व मिलता था वह घट के 6.94 करोड़ हो गयी। पुणे डिवीजन की कमाई 1 करोड़ से घट के महज 1 लाख प्रति दिन रह गयी। अब चुकी यह सरकारी विभाग है इसलिए बैल आउट पैकेज का रास्ता खुला हुआ था। अब इतने घाटे में जाने के बाद ,95 हजार कर्मचारीओ का पगार कहा से आएगा। तकरीबन 300 करोड़ तो सिर्फ सैलरी के नाम पर खर्ज करना पडता है । तो तीन किस्तों में राज्य सरकार ने खैरात बाटी ताकि वेतन का भुगतान समय पर हो सके। कुल 1200 करोड़ से ज्यादा का बैल आउट पैकेज यानि खैरात परिवहन सेवा को राज्य सरकार से मिल चूका है। शायद आगे भी मिलेगा। पर यह जो भी नुक्सान हो रहा है और जो भी रकम आ रही है वह आपके और मेरे जेब से कर के रूप में ही आ रहा है। अब जो कोविद नियम है उसके पीछे के विज्ञानं पर न किसी ने दिमाग दौडाना है न सवाल खडे करने है ,जैसे बादशाह का हुकम है की कितने भी नुक्सान में डूब जाओ , हुकम की न फरमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारी टीम ने कई बार इन बसों में सवारी की पर साफ सफाई अपने न्यूनतम स्तर पर ही नजर आया । यात्रा आमंत्रण से खास बातचीत में प्रबंध संचालक श्री शेखर चन्ने ने क्या कहा उसे बिंदु दर बिंदु समझते है

शेखर चन्ने

प्रबंध संचालक, एमआरएसटीसी

माल परिवहन सेवा से अतिरिक्त कमाई का रास्ता देख रहे है। खुद के पेट्रोल पंप लगा के पेट्रोल बेच के आमदनी बढाने का लक्ष्य है।इसमें हमने इंडियन आयल कारपोरेशन के साथ भी करार किया है। हमारे पास जमीन है। उसके माध्यम से आय बढाने की तरफ देख रहे है। खर्चा कम करने की भी कोशिश है। हमारा प्रमुख खर्चा डीजल है। इसमें डीजल की जगह CNG या LNG की तरफ जा रहे है। अभी हमने 500 गाडी LNG में बदल रहे है। 1000 गाडी को CNG में बदल रहे है । हम किराय पर भी गाडी ले रहे है ताकि पूंजीगत व्यय हमारी तरफ से न हो। प्रति किलोमीटर में गाडी किराय में लेने से भी हमारी बचत हो जाएगी। घाटे को पूरा करने के लिए टिकट के दाम नहीं बढेगा। टिकट के दाम बस की कीमत बढने या डीजल के दाम बढ़ ने से जोडा गया है। यह तय फार्मूला है जिसमे गाडी के पार्ट्स की कीमत या डीजल की एक तयशुदा कीमत के आकलन से बढेगा ।

हमारा विश्लेषण : राज्य परिवहन की जिम्मेदारी संभाल रहे शेखर सर आश्वासन तो दे रहे है की कीमते नहीं बढेगी और दुसरे रास्तो से इस घाटे को पूरा कर लिया जायेगा। पर बात इतनी सी नहीं है। हम शुरू से एक ही सवाल उठा रहे है की जो कोविद प्रोटोकॉल बनाये जा रहे है उसकी वैज्ञानिक प्रमाणिकता क्या है। क्युकी अब तक किसी भी जर्नल में साबित नहीं हुआ है की बस में लागु प्रोटोकॉल से कोविद का संक्रमण कम होगा। न ही कोई ऐसा 'शोध हुआ जो साबित करे की इस प्रोटोकॉल के कारण इतने प्रतिशत संक्रमण कम हुआ है। जबकि इसी प्रोटोकॉल के चलते बस कारपोरेशन को 2750 करोड़ का नुक्सान हुआ है। शेखर सर कहते है की प्रोटोकॉल इसलिए ताकि भीड भाड़ न हो ,सामाजिक दुरी बनी रहे ,आपकी बात सही है तो राजनैतिक रैली और किसान पंचायत में लाखो की भीड़ में कोरोना कहा लुप्त हो जाता है। सरकारी बस जनता की है और जनता के पैसो से चलती है। उसी जनता को इस सुविधा से रोका गया। आखिर पैसे हमारे ही है और हम ही बस में नहीं चढ़ सकते है और घाटा भी हम ही पूरा कर के दे।आखिर किसी को आगे आकर जवाब देना होगा। हम पूछ रहे है क्युकी पूछना जरूरी है। ताकि सरकारी उपक्रम अपने घाटे का रोना रोने से पहले देख ले की वास्तिविकता क्या है और क्या है जो अभी भी व्यावहारिक नहीं है।

अनिल गर्ग

अध्यक्ष , स्कूल बस ओनर एसोसिएशन , महाराष्ट्र

हमारे एक बस में तीन स्टाफ रहते है, एक सफाई कर्मचारी , एक महिला परिचारक और एक ड्राइवर, इसके अलावा हर दस बस पर एक मैनेजर। मुंबई में प्रदुषण नियंत्रण के कारण नियम है की आठ साल से ज्यादा बस नहीं चला सकते है और अगर CNG है तो पंद्रह साल की अनुमति है । हमने प्रधानमंत्री तक पचासो चिट्ठी भेजी , की हमे कुछ तो सुविधा दो। हमारी कुछ भी मदद नहीं की जबकि सबसे ज्यादा पैसा परिवहन उद्योग से आता है। हमारी एक बस की खरीदी 29 लाख के आस पास रहती है। इस तरह से पांच साल में लोन की भरपाई होती है और तीन साल का मुनाफा हमे मिल पाता है। हमने सरकार से गुजारिश की है दो साल आपके कारण बस नहीं चली तो आठ साल की मियाद को बढा के दस साल करो। सरकार ने सिर्फ 6 महीने के लिए टैक्स माफ किया जबकी हमारा सारा कारोबार बंद है तो टैक्स किस बात का। डेढ़साल से बंद बस की हालत ऐसी है की दो चार लाख तो प्रति बस खर्च आएगा , तभी बस चल पायेगी। मौजूदा समय में 45 हजार स्कूल बस महाराष्ट्र में और 8 हजार मुंबई में है। तालाबंदी के शुरू में हमने कुछ कामगार को पचास प्रतिशत पगार दिया इस उम्मीद से की जल्द ही स्कूल खुलेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं और काफी कर्मचारी काम छोड़ के चले गए। हालत इतने बुरे हो गए है की बस चालक हमाल गिरी कर रहे ,सब्जी बेच रहे है , दूध की थैली बेच रहे है और कोई धोबी बन गया है। इस बीच आत्महत्या के भी मामले देखे गए है। पर सरकार की आखे खुल ही नहीं रही है।

मुंबई को लेकर योजना / दिल्ली मॉडल की हकीकत

प्रीति मेनन

राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, आप

मुंबई में महिला यात्री को मिलेगा बस में फ्री टिकट दिल्ली के तर्ज पर , जबकि बेस्ट का सालाना घाटा 1800 करोड़ के करीब है। प्रीति मेनोन मानती है की बेस्ट का घाटा घोटालो के चलते है। इस हिसाब से दिल्ली में बस का सालाना घाटा 2018-19 में 1600 करोड़ था और घाटे में जाने वाली देश की स्टेट ट्रांसपोर्ट में दिल्ली की बस सेवा नंबर एक पर है।

मुंबई में औसतन चार से पांच महीना बारिश का रहता है और जल भराव एक आम समस्या है। आप का मानना है की मुंबई के बारिश में जल भराव भी यहाँ के सिस्टम की अनदेखी के कारण है। जबकि दिल्ली में मुंबई के मुकाबले बहुत कम बारिश होती है फिर भी वहा के अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे में पानी भर जाता है। कई इलाको के अंडरपास पानी में बस डूब जाती है। पीडब्ल्यूडी विभाग को सितम्बर के महीने में 40 से जयादा जल भराव की शिकायते मिली।

प्रीति मेनन का मानना है की मुंबई के कॉर्पोरेटर का एक ही काम है मुंबई को नोच नोच के खाना । दिल्ली मॉडल के तर्ज पर आप के पास 20 विधायक पंजाब में है। जबकि हाल ही में आप के जनरल सेक्रेटरी पंकज गुप्ता पर इ डी की जाँच मनी लॉन्डरिंग के मामले में चल रही है।

मुंबई की नदिओ में बढता प्रदुषण एक गंभीर विषय है। 2015 में प्रकाशित रिपोर्ट कहती है की मीठी नदी सौ प्रतिशत मल से भरी हुई है। प्रीति मेनन इसके लिए भी योजना बना रही है। पर दिल्ली के नदिओं का हाल भी जान लीजिये। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है की यमुना नदी किसी बहते गंदे नाले से कम नहीं है। तीसरी बार आप सत्ता में आई पर यमुना की सफाई आज तक नहीं हो पाई। साल 2020 में एक तरफ जहा मुंबई महानगरपालिका ने मीठी नदी के लिए 569 करोड़ की राशि आबंटित किया है वही दिल्ली की सरकार ने यमुना नदी तीन साल में साफ करने के लिए 2074 करोड़ की राशि खर्च करने की योजना बनाई है।

Watch Asatya Bharat You Tube Channel for the complete interview

प्रजा फॉउण्डेशंन के अनुसार नब्बे प्रतिशत पार्षद का प्रदर्शन घटिया

मुंबई महानगपालिका के 24 वार्ड से 232 पार्षद चुन के आते है। इसके आलावा महानगपालिका के काम काज को सँभालने के लिए कुल 1.5 लाख कर्मचारी है। इन सबके आलावा महानगरपालिका का सालाना बजट 30 हजार करोड़ से 37 हजार करोड़ के बीच रहता है। वर्ष दो हजार सत्रह को पार्षद की सैलरी दस हजार से बढा के 25 हजार कर दी गयी। हलाकि समाजवादी पार्टी के रईस शेख चाहते थे की वेतन 50 हजार कर दिया जाये।

इन सबके के बावजूद अगर एक करोड़ पचास लाख से जयादा आबादी वाली इस शहर में अनियमिता रह जाये तो जनता की उपेक्षा पर सवाल तो उठेंगे ही। प्रजा फाउंडेशन ने पाया की सिर्फ 50 प्रतिशत पार्षदों ने सवाल पूछे वह भी 17 सवाल प्रति वर्ष। 99 प्रतिशत पार्षद नागरिको की शिकायत सुनाने को प्राथमिकता नहीं दी

प्रजा फॉउण्डेशंन की जमीनी हकीकत जानने के लिए हमारी टीम ने मालवणी के अम्बुजवाडी का दौरा किया। एक लाख प्रवासी मजदूर का यह इलाका बेहद ही अमानवीय स्थिति में है। हमने इसी तरह से धारावी का दौरा किया , बांद्रा झोपड़पट्टी भी गए और बोरीवली के दौलत नगर भी गए। सभी जगह स्थिति में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। कोरोना काल में जयादातर पार्षद नदारत ही रहे और तालाबंदी की मार झेल रहे मुम्बईकर अपने किये खुद ही समाधान ढूंढ रहे थे।

मनोज देसाई

एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मराठा मंदिर

आम जनता से भी अपील है की वह भी हमारे समर्थन में मुख्यमंत्री को लिखे की उन्हें थिएटर की जरूरत है। मेरे कई सारे कामगार राजीनामा देकर हमेशा के लिए चले गए है।उन्होंने अपने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर दिया है। वह वापस नहीं आने वाले है। जब भी थिएटर शुरू होगा तो हमे वापस नए भर्ती करनी पडेगी। आज सिनेमा जगत को वापस अपने पुराने स्वरुप में आने में कम से कम चार साल लग जायेंगे, वह भी तबजब बेहतरीन फिल्मे आएँगी। और सबसे बडी चुनौती OTT मीडियम है। बडी से बडी फिल्मे वह पर देखि जा रही है। हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा की हम वापस जनता को थिएटर में ला सके। एक बार अगर पब्लिक की आदत छूट जाती है थिएटर आने को लेकर तो वापस आदत दिलाने में वक्त लगता है। थिएटर ओनर एसोसिएशन ने सरकार से काफी बातचीत की है। पर हमारी तरफ कोई धयान नहीं दिया गया। बस इतना ही कहते है की अभी तो कोरोना चल रहा है। सोचते है।

Watch Asatya Bharat You Tube Channel for the complete interview

होटल व्यवसाय के आये बुरे दिन

- आकडो में समझते है तालाबंदी ने खान पान या रेस्टोरेंट धंधे को किस तरह से चौपट कर दिया है।
- 40 प्रतिशत खाने के दुकानों में हमेशा के लिए ताला लग चूका है।
- अतिथि-सत्कार उद्योग को 1.30 ट्रिलियन रुपये का नुक्सान हो चूका है
- 15 लाख लोग बेरोजगार हो गए है
- अतिथि-सत्कार उद्योग पर 60 हजार करोड़ रुपये का बकाया है
- महाराष्ट्र में 2 लाख 10 हजार रेस्टोरेंट है जिनमे से 50 प्रतिशत बंद होने के कगार पर है।
- मौजूदा समय में रेस्टोरेंट उद्योग को केवल 30 प्रतिशत का राजस्व प्राप्त हो रहा है।

सुकेश शेट्टी

महासचिव , इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन

दुसरे लहर के तालाबंदी से विमान सेवा और अतिथि उद्योग सबसे जयादा प्रभावित हुए है। 35 प्रतिशत खाने के होटल शायद ही अब खुल पाए। BAR केलिए अभी भी स्थिति जटिल है क्युकी देर रात तक खोले रखने की अनुमति नहीं मिली है। व्यावसायिक प्रतिष्ठान के आस पास चलने वाले खाने के दुकानों की बुरी हालत है क्युकी अभी भी लोग घर से ही काम कर रहे है। लम्बे समय के लिए रोजगार की समस्या बनी रहेगी। घर बैठ के खाना मंगाने का चलन जोर पकड़ेगा। बिजनेस करने के तरीको में भरी बदलाव देखने को मिलेगा।

प्रणव रूंगटा

प्रमुख, मुंबई भाग, राष्ट्रीय रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया

पिछले डेढ सालो में तकरीबन 183 दिन हमने कारोबार बंद रखा है। और जब खोलने की इजाजत मिली तो कई तरह के प्रतिबन्ध हम पर लगाए गए। इनमे प्रमुख है सभी कामगार को टीके का दोनों डोज आवशयक है। इसके कारन 18 से 45 साल के हमारे 50% कर्मचारी बेरोजगार हो गए । हमारी मांग है की रेस्टोरेंट को रात्रि दस बजे से बढ़ा के डेढ़ बजे तक कर दिया जाये। इसी तरह से हमे कम से कम पचास से पचहत्तर प्रतिशत बैठा के खिलने की अनुमति दी जाये। इसके आलावा रेस्टोरेंट पर लगने वाले सम्पति कर में भी छूट दी जाये।

गैर निष्पादित मुंबई

उधार लेने की आई नौबत। ठाणे महानगरपालिका के खजाने में 95 करोड़ बचे है जिसमे से 75 करोड़ वेतन पर खर्च होगा । इसलिए एक हजार करोड़ कर्ज लेने की योजना बनाई जा रही है। हो सकता है इसमें कुछ नया जुड़ गया हो पर यह हाल है ठाणे के महानगपालिका का।

Franchise Opportunity

CONTACT

90494 87 878

पुणे की सुप्रसिद्ध

काळजे मिसळ हाउस®

COME AND EXPERIENCE IT

CALL US FOR BEVERAGES OUTLET LAUNCHING ON NEW YEAR 2022

Benefit to get an franchise

- Fastest growing misal brand among family.
- Great taste and assurance of quality.
- Low investment high returns.
- Unique trendy menu.
- We provide training, marketing, branding and staff support.
- Raw material provided by us.
- Own production strength.

ADDRESS

SHOP NO B 1 PRIVIA MALL
NEAR PCMC RTO SECTOR 6
MOSHI PRADHIKARAN
PUNE 411062

Follow us : @kaljemisalhouse

असली पावर है किसके पास, नौकरशाह या जनता के चुने हुए नेताओ के पास। तीन बार पार्षद और एक बार विधायक रह चुके फैयाज अहमद से सीधा सवाल।

फैयाज अहमद

मुंबई अध्यक्ष, एआईएमआईएम

जवाब : बम्बई की जनता जब टैक्स देती है तो नौकरशाह को पगार आता है ।मैं नहीं मानता की कमिश्नर के हाथो में सब पावर है। मैं एक बार विधायक और तीन बार पार्षद रह चूका हु। अगर वह काम नहीं करेंगे तो यह पावर हमारे पास है की उनको बदल दे। यह बात नहीं होती है। जनता अपने पावर को समझे तो समाधान मिलेगा। ब्यूरोक्रैट के पास सलाह देने का पावर है पर हमारे पास स्टैंडिंग कमिटी है । सब फैसले हम करते है ।हम आगे बढाते है। फिर वह फैसला लेते है। नगरपालिका में जो काम होता है वह अलग अलग कमिटी के माध्यम से होता है । आयुक्त का काम ओके करके आगे बढाना होता है।

दावों की जमीनी हकीकत हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुहासिनी साकिर से समझते है।

वर्ष 2019 में मैं महिलाओ के रोजगार को लेकर आठ महानगपालिका में गयी। मैंने गरीब महिलाओ को रोजगार मिले इस पर एक योजना मेयर को दी । इसमें विरार,भायंदर, ठाणे,नवी मुंबई और उल्हासनगर के मेयर के साथ सीधी बातचीत शामिल थी। सभी जगह जवाब एक ही था की फैसला और निर्णय कमिश्नर के हाथो में है।मेयर से अगर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल भी जाती है तो भी तब तक कुछ नहीं हो सकेगा जब तक कमिश्नर उसे मंजूर नहीं करता है। उल्हासनगर में मेयर के कहने और पत्राचार के बाद भी आयुक्त ने प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढाया। साल भर के मेहनत के बाद जो बात समझ में आई की वोट हम जिन्हे देते है उनके हाथ बंधे है आयुक्त के आगे। कोविद के समय भी तालाबंदी के सारे निर्णयों पर हस्ताक्षर नौकरशाह के ही थे। पर आप इस बार पूछे जब वोट मांगने कोई आये की वोट आपको क्यों दे अगर आयुक्त के भरोसे ही पूरा सिस्टम चल रहा है तो । और इसमें आप डेमोक्रेसी जरूर ढूंढ के रखे । वह मिले तो बताइयेगा ।

चलते चलते

मैं मुंबई के मेयर और आयुक्त से निवेदन करना चाहूंगा की जब आप कोविद की लडाई में आम आदमी के सारे त्योहार बंद करा रहे है , ट्रेनों में पाबन्दी लगा रहे है,दुकाने बंद करा रहे है ,जबरदस्ती टिका थोप रहे है ,जबरदस्ती RTPCR अनिवार्य कर रहे है तो आप मुंबई को आश्वासन दे की इस बार महानगरपालिका के चुनाव में एक भी पब्लिक रैली नहीं होगी, कोई रोड शो नहीं होगा , कोई घर घर कैंपेन नहीं होगा, कही भी पांच से अधिक पार्टी के सवम सेवक एकत्रित नहीं होंगे, किसी भी तरह का लाउडस्पीकर नहीं बजेगा,एक महीना धारा 144 लागु रहेगी औरकिसी भी तरह के बैनर और पोस्टर नहीं लगाए जायेंगे। किसी भी तरह का प्रेस कांफ्रेंस नहीं होगा और ना हीं मैनिफेस्टो जारी करने सम्बंधित कार्यक्रम होंगे। सिर्फ नेता सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के जरिये ही अपनी बात रखेंगे।बहुत हुआ तो आप ऑनलाइन आकर वीडियो कांफ्रेंस के जरिये जनता से मुखातिब होंगे। और चुनाव जितने के बाद किसी भी तरह के जीत के जलूस नहीं निकलेगा। न कोई ढोल बाजा बजेगा।

अनिल नागरथ

सचिव , इम्पा

जो सीरियल ऑन थे उनको मुंबई से बाहर जाना पडा, काम की कमी के कारन जयादार कामगार आपने गाँव लौट गए है। डांसर , एक्टर, प्रोडूसर सभी के लिए अनिश्चितता का समय था। महाराष्ट्र के आलावा सभी जगह थिएटर खुल चुके है, जिसके कारण थिएटर से जुडे दुसरे रोजगार जैसे कैंटीन मालिक, पार्किंग का काम करने वाले सब बेरोजगार हो गए है। पता नहीं क्यों सरकार इस फिल्म बिजनेस को बंद कराने में तुली हुई है।

RNI No :
HRAHIN/2017/72144

बोइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम क्या है? अगर एक मेढक को पानी से भरे बर्तन में रख दे और धीरे धीरे उस पानी को गरम करने लगे तो मेढक पानी में ही रहेगा और जब पानी का तापमान ज्यादा गरम हो जायेगा तो मेढक भी उसी गरम पानी में मर जायेगा। इसी तरह से पिछले साल जनता कर्फ्यू से बात शुरू हुई थी, फिर २१ दिन का तालाबंदी, फिर तीन महीने बढा दिया गया और अब दो साल होने वाले है।

२०१९ से पहले किसी ने सोचा था की उसका घर ही उसका जेल बन जायेगा। पर हम पर मेढक वाली टेक्निक आजमाई गयी और धीरे धीरे हमको गुलामी की आदत डलवाई गयी। पहले दिन अगर बोल दिया जाता की दुबारा कभी सामान्य नहीं होगा तो जनता उसे कभी नहीं स्वीकारती।

डॉ. बिस्वरूप रॉय चौधरी

विश्व विख्यात चिकित्सा पोषण विशेषज्ञ